अपनी बात

ग्यारहवें पंचेन लामा को रिहा करे चीन

ग्यारहवें पंचेन लामा गेदुन छोक्यी निमा के 25वें जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली में 25 अप्रैल 2014 को आयोजित विशेष कार्यक्रम में तिब्बतियों के साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न तिब्बत समर्थक सामाजिक–राजनीतिक–आध्यात्मिक संगठनों ने एक स्वर में मांग की कि चीन सरकार ग्यारहवें पंचेन लामा को यथाशीघ्र रिहा करे। ज्ञातव्य है कि लगभग बीस वर्ष पहले उन्हें चीन की सरकार ने अवैध रूप से बंदी बना लिया था। तब वे महज चार–पांच साल के बालक थे। उस समय उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सबसे कम उम्र का कैदी बताया था। तब से लेकर अब तक उनके बारे में तथा उनके परिवार के बारे में तिब्बत पर अवैध नियन्त्रण स्थापित करने वाली साम्राज्यवादी चीन सरकार ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बताया है। इससे सभी तिब्बतियों एवं तिब्बत समर्थकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। वे सभी लगातार मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपील कर रहे हैं कि चीन सरकार पर दबाव बनाकर पंचेन लामा जी एवं उनके परिवार को चीनी चंगुल से मुक्त कराया जाए।

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपनी व्यस्तता के बावजूद कई राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि ''मध्यम मार्ग'' संस्था द्वारा आयोजित विशाल पद यात्रा एवं सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। इससे साफ पता चलता है कि तिब्बत के प्रश्न पर सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल एकमत हैं। इसी तरह अगले दिन जंतर–मंतर पर ही आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी आध्यात्मिक पंथों के प्रमुख धर्मगुरू एवं चिंतक शामिल हुए। ये भी ग्यारहवें पंचेन लामा जी की अवैध गिरफ्तारी से चिंतित हैं। उनके द्वारा सामूहिक प्रार्थना की गई और ''मध्यम मार्ग'' संस्था को आश्वासन दिया गया कि सभी आध्यात्मिक पंथों के धर्मगुरू एकजूट होकर उसके संघर्ष में साथ देते रहेंगे।

चीन सरकार को चाहिए कि वह ग्यारहवें पंचेन लामा को यथाशीघ्र रिहा करे। इसके विपरीत वह तिब्बत में शांतिपूर्ण आंदोलनकारी तिब्बतियों पर तरह–तरह से अत्याचार कर रही है। इसी का नतीजा है कि तिब्बती आंदोलनकारी आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे हैं। गत एक–दो वर्षों में ही लगभग डेढ़ सौ तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। इसी अप्रैल माह में भी एक तिब्बती ने आत्मदाह करके अपना बलिदान किया है। चीन सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ यह बहुत ही कठोर किस्म का बलिदान है। यह मामूली आत्मदाह नहीं है। हर बार की तरह 27 अप्रैल को तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री (सिक्योंग) डॉ. लोबसांग सांगे, तिब्बती संसद के स्पीकर पेम्पा त्सेरिंग तथा अन्य निर्वासित तिब्बती प्रतिनिधियों ने तिब्बती आंदोलनकारियों से अपील की कि वे आत्मदाह मत करें। बौद्ध दर्शन के अनुसार अपने खिलाफ की गई हिंसा भी जायज नहीं है। मध्यम मार्ग संस्था द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रमों में बार–बार इस प्रकार की अपील की गई।

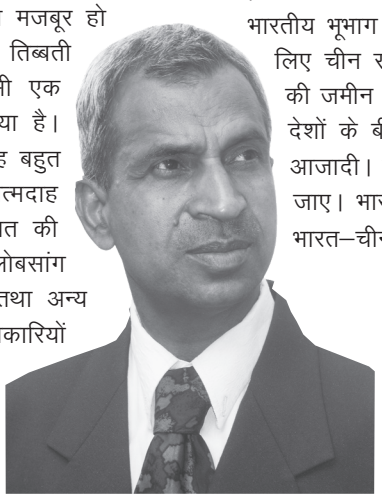

चीन सरकार के दबाव में नेपाल सरकार भी तिब्बतियों पर घोर अत्याचार कर रही है। इसका खुलासा ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा निर्मित एक वीडियो फिल्म में किया गया है। नेपाल में तिब्बतियों को अनेक प्रकार की पाबंदियों में रहना पड़ रहा है। अपने देश से बाहर रह रहे तिब्बतियों पर भी चीन सरकार दमनचक्र चला रही है। यह नेपाल की संप्रभुता का भी अनादर है। चीन सरकार का इस प्रकार का प्रत्येक कृत्य अमानवीय, अलोकतांत्रिक, कानून विरोधी तथा निंदनीय है। अपनी तिब्बत विरोधी गतिविधियों में उसे किसी तरह की अड़चन पसंद नहीं है। वह इसे चीन का आंतरिक मामला बताती है, जबकि तिब्बत का मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून का मामला है। चीन को तिब्बत से बाहर जरूर जाना होगा, क्योंकि उसने अवैध तरीके से तिब्बत को अपने कब्जे में ले रखा है। मध्यम मार्ग संस्था की मांग है कि चीन सरकार तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान कर दे। तिब्बत को चीन के अंतर्गत ही स्वशासन का अधिकार मिले। ऐसी मांग चीन के अपने संविधान एवं कानून के अनुकूल है।

चीन सरकार के लिए उचित यही होगा कि वह हठ छोड़कर विश्व जनमत का आदर करते हुए पंचेन लामा जी को रिहा करे। वह तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देकर वहां की खराब हालत को दूर करे। इसके लिए उसे तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों से सार्थक वार्ता करनी चाहिए। भारत ऐसी वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तिब्बत समस्या के समाधान में ही भारत की सुरक्षा तथा भारत–चीन संबंधों की मधुरता निहित है।

भारत अपने आप को तथाकथित ''हिन्दी–चीनी भाई–भाई'' तथा भारत के लिए पंचशूल प्रमाणित हो चुके ''पंचशील'' के मायाजाल से मुक्त करे। चीन द्वारा भारत की हजारों वर्गमील जमीन हड़पी जा चुकी है। अब भी चीन सरकार भारत के कई इलाकों पर अपने दावे कर रही है। वह भारत की एकता–अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देती हुई भारतीय भूभाग में घुसपैठ कर रही है। भारत को कमजोर करने के लिए चीन सरकार भारत को चारों ओर से घेर चुकी है। तिब्बत की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच विश्वसनीय दोस्ती के लिए जरूरी है तिब्बत की आजादी। पहले की तरह फिर से तिब्बत को बफर स्टेट बनाया जाए। भारत एवं चीन के बीच स्वतंत्र तिब्बत का अस्तित्व ही भारत–चीन संबंधों को मजबूत करेगा। ◆

प्रो0 श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खेतड़ी (राज.)
ek-&9829806065] 8764060406
E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

हिमाचल प्रदेश में चार नए तिब्बत समर्थक संगठनों की स्थापना

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 11 अप्रैल, 2014)

आचार्य येशी फुंत्सोक के साथ बीर/चाउंट्रा के नवगठित तिब्बत समर्थक संगठन के सदस्य

हिमाचल प्रदेश के बीर/चाउंट्रा, मंडी, रेवालसर और कुल्लू–मनाली इलाकों में चार नए तिब्बत समर्थक संगठनों की स्थापना की गई है। इन तिब्बत समर्थक संगठनों की स्थापना निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य आचार्य येशी फुंत्सोक और श्री डोलकर क्याप ने स्थानीय तिब्बती कल्याण कार्यालय के समन्वय से किया है।

इन नए तिब्बत समर्थक संगठनों में भारत–तिब्बत मैत्री संघ बीर, चाउंट्रा और जोगिंदर नगर, भारत–तिब्बत मैत्री संघ मंडी एवं सुरेंदर नगर, तिब्बत सपोर्ट ग्रुप (टीएसजी) रेवालसर और तिब्बत सपोर्ट ग्रुप कुल्लू–मनाली शामिल हैं। इन तिब्बत समर्थक संगठनों के अध्यक्ष क्रमशः श्री पंकज जामवाल, सुश्री सुशीला शुंकला, श्री बंसी लाल और सुश्री छेमी डोलमा हैं।

हिमाचल प्रदेश के इन चारों इलाकों में टीएसजी का गठन पहली बार किया गया है और इसके लिए तिब्बती बस्ती कार्यालय और स्थानीय तिब्बतियों और भारतीयों ने गंभीरता से प्रयास किया था। इन टीएसजी के सदस्यों ने तिब्बत के मसले पर अपना समर्थन देते हुए हुए वहां के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमालय भारत के कई राज्यों के लिए मुख्य जल स्रोत रहा है।

तिब्बत समर्थक संगठनों की स्थापना खासकर तिब्बत मसले के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हुई है। इनके द्वारा तिब्बत मसले को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह संगठन स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भी तिब्बती आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वे तिब्बतियों और स्थानीय भारतीयों के बीच सौहादपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए भी काम करेंगे।

तिब्बत आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन जताने के लिए इन संगठनों के द्वारा सेमिनार, सम्मेलन, विरोध रैलियों आदि घटनाओं और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अगले वर्षों में इन संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

भारत में विभिन्न शाखाओं के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर करीब 20 तिब्बत समर्थक संगठन हैं। इनका मुख्य उद्देश्य तिब्बत के मसले पर एक शांतिपूर्ण समाधान तलाशना है। इस इलाके के आधिकारिक दौरे पर आए आदरणीय आचार्य येशी फुंत्सोक ने इन तिब्बत समर्थक संगठनों के नेताओं और सदस्यों से मुलाकात की। अपने भाषण में आचार्य येशी फुंत्सोक ने कहा कि भारत और तिब्बत सबसे करीबी पड़ोसी देश हैं। भारत में आजादी हासिल होने से पहले से ही तिब्बत के साथ इसके व्यापारिक रिश्ते हैं। उन महान भारतीय गुरुओं की बदौलत ही दुनिया भर में तिब्बती बौद्ध धर्म फैला है जिन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी।

निचली जलधाराओं वाले देश खासकर भारत पर तिब्बती पर्यावरण का सीधा असर पड़ता है। तिब्बत का मसला एक अंतरराष्ट्रीय मसला है और काफी हद तक यह भारत के अपने राष्ट्रीय हित में भी है। उन्होंने कहा कि बहुत से भारतीय नेताओं ने गंभीरता से और वाजिब तरीके से तिब्बत आंदोलन का समर्थन किया था और उन्होंने भारत की आज़ादी के शुरुआती दिनों में संसद में इस मसले का उठाया था। ◆

चीन के साथ व्यापार की जगह जर्मनी, फ्रांस के लोगों ने दी मानवाधिकार, तिब्बत मसले को तरजीह

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 27 मार्च, 2014)

वाशिंगटन आधारित तिब्बत समर्थक संगठन ने 24 मार्च को कहा है कि उसके द्वारा कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि फ्रांस और जर्मनी की जनता का भारी बहुमत यह चाहता है कि उनके नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के समय मानवाधिकार और तिब्बत जैसे मसले उठाएं। नीदरलैंड के शहर हेग में नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के बाद शी 24 मार्च को ही फ्रांस पहुंचे थे। यूरोप की चार देशों के दौरे पर निकले शी जर्मनी और बेल्जियम भी जाएंगे।

इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) ने कहा है कि यह जनमत सर्वेक्षण उसने कराया था और इसे फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपीनियन ने 10 से 14 मार्च के बीच किया था। इसमें फ्रांस के 1,000 नागरिकों और जर्मनी के 1,003 नागरिकों से बातचीत की गई थी। इस सर्वेक्षण में कहा गया है, "फ्रांस के 90 फीसदी और जर्मनी के 92 फीसदी नागरिकों ने तिब्बत के मसले के लिए चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव शी जिनपिंग और दलाई लामा के बीच बातचीत का समर्थन किया है ताकि तिब्बत मसले का कोई समाधान निकाला जा सके।

इसके अलावा, इस सर्वे से यह पता चला कि "इन दो बड़े यूरोपीय देशों के नागरिकों ने चीन के साथ व्यापारिक सौदों को आगे बढ़ाने की जगह इस बात को ज्यादा तरजीह दी कि उनके नेता तिब्बत और मानवाधिकार का मसला उठाएं।" इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में आईसीटी के अध्यक्ष श्री मटेओ मेकास्सी ने कहा, "यूरोपीय संघ के नेता अपने नागरिकों की विचारधारा को नजरअंदाज नहीं कर सकते और उन्हें साफ तौर से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा तथा तिब्बत में मानवाधिकार संकट जैसे मसलों के प्रति शी की यात्रा के दौरान अपना समर्थन प्रकट करना चाहिए। चीन के साथ हमारे रिश्तों में जो कुछ भी दांव पर है वह किसी व्यापारिक रिश्ते या उनके बाजार तक सीधे पहुंच से परे है, यह एक बढ़ते अधिनायकवादी देश के साथ रिश्ता है जो उस दुनिया की प्रकृति और आकार तय करेगा जिसमें हम रहना चाहते हैं।" सर्वे में शामिल 83 फीसदी लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंडे और जर्मनी की चांसलर मर्केल को दलाई लामा को आधिकारिक रूप से अपने–अपने देशों में आमंत्रित करना चाहिए। ◆

चीनी शासन के तहत हुए 131वें आत्मदाह की घटना मे तिब्बती युवक की मौत

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 17 अप्रैल, 2014)

चीन लगातार इससे इंकार कर रहा है कि अधिकृत तिब्बत में किसी तरह की कोई समस्या है, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शन के तहत आत्मदाह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गत 15 अप्रैल को सिचुआन प्रांत के कार्डजे प्रशासनिक क्षेत्र के ताउ काउंटी में आत्मदाह की एक और घटना हुई। खबरों के अनुसार 32 वर्षीय थिनले नामग्याल ने काउंटी के खांगसार टाउनशिप में दोपहर को खुद को आग लगा लिया और इसके कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। चीन ने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी और उस इलाके के सभी संचार एवं यातायात संपर्कों को काट दिया गया।

बताया जाता है कि आग तत्काल ही तेजी से फैल गई जिसकी वजह से इस व्यक्ति की जल्दी मौत हो गई। रेडियो फ्री एशिया (आरएफए, वाशिंगटन) द्वारा 15 अप्रैल को जारी खबर में एक सूत्र ने बताया, "उन्होंने चीनी नीति और शासन (तिब्बती जनसंख्या वाले इलाकों) के विरोध में आत्मदाह कर लिया।

घटनास्थल के पास मौजूद तिब्बतियों ने तत्काल ही इस व्यक्ति के अवशेष गोंथाल मठ लेकर गए और कुछ धार्मिक क्रिया कर्म करने के बाद उसे मृतक के परिवार को सौंप दिया।

इस घटना के साथ ही चीनी शासन वाले तिब्बत में आत्मदाह करने वालों की संख्या 131 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 112 की मौत हो गई है। इसके पहले कार्डजे प्रशासनिक क्षेत्र में ही स्थित बथांग काउंटी के बा छोडे मठ के निकट 29 मार्च को डोलमा नाम की एक भिक्षुणी ने आत्मदाह कर लिया था। ◆

चीन ने आस्ट्रेलिया में अपने विद्यार्थियों की जासूसी कराई और दूसरों पर भी निगरानी

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 22 अप्रैल)

ऑस्ट्रेलिया में चीनी विद्यार्थी

अपने आर्थिक सहयोग वाले विद्यार्थी संगठनों की स्थापना के द्वारा चीन ने आस्ट्रेलिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में जासूसों का एक जाल बिछा लिया है ताकि वहां चीन की मुख्यभूमि से आए 90,000 विद्यार्थियों की गतिविधियों की निगरानी की जा सके और उन पर अंकुश रखा जा सके। एसएमएच डॉट कॉम एयू ने 21 अप्रैल को यह खबर दी है। चीन के अधिनायकवादी शासकों को इस बात की चिंता है कि ये विद्यार्थी उन विचारों और गतिविधियों के संपर्क में आ सकते हैं जो उनके मातृभूमि में नहीं मिलतीं। इस नेटवर्क के माध्यम से चीन दूसरे नस्ल के लोगों जैसे तिब्बतियों आदि पर भी निगरानी रखने की कोशिश कर रहा है जो अपनी मातृभूमि पर चीनी कब्जे का विरोध कर रहे हैं।

खबर में बताया गया है कि एक मामले में तो सुरक्षा अधिकारियों ने एक विद्यार्थी के चीन स्थित मां–बाप को चेतावनी दी कि वे अपने बेटे की गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। मुखबिरों ने सूचना दी थी कि वह लड़का आस्ट्रेलिया में दलाई लामा को देखने गया था।

एक अन्य मामले की जानकारी देते हुए आस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के सीनियर लेक्चरर ने कहा, "मुझसे चीन में चार बार पूछताछ की गई।" उन्होंने एनएसडब्ल्यू विश्वविद्यालय में लोकतंत्र पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया था जिसके बारे में चीन की मुख्य जासूसी एजेंसी ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई, मैं उस महिला का नाम बता सकता हूं जिसने मुझे यह रिपोर्ट भेजी है।" खबर के अनुसार चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने फेयरफैक्स मीडिया से इस बात की पुष्टि कर दी है कि आस्ट्रेलिया में चीनी समुदाय के लोगों पर नजर रखने के लिए मुखबिरों का जाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि चीन के "मुख्य हितों" की रक्षा की जा सके।

चीन द्वारा जासूसी पर किए जाने वाले खर्च और जासूसों की संख्या का हवाला देते हुए एक आस्ट्रेलियाई अधिकारी ने कहा, "सिडनी विश्वविद्यालय में हमसे ज्यादा संसाधन तो उनके पास है। खबर के अनुसार खुल्लमखुल्ला राजनयिक मिशनों के एजुकेशन काउंसलर चीन के स्टुडेंट्स के साथ मिलकर ऐसे संगठन बनाते हैं जिनके द्वारा वे चीनी विद्यार्थियों का सहयोग कर सकें। हालांकि सहयोग सेवा देने के अलावा चीन सरकार के सहयोग से चलने वाले ये संगठन खुफिया जानकारी भी देते हैं और इनके द्वारा चीन सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

खबर में चीनी राजदूत छेन योंगलिन के हवाले से कहा गया है कि चीनी राजनयिक आस्ट्रेलिया के हर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का गठन करते हैं, उनके नेता की नियुक्ति करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनको धन की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा, "नेताओं का एयरपोर्ट पर स्वागत करने, किसी स्थान से विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों के लोगों को हटाने और सूचनाएं जुटाने के लिहाज से ऐसे विद्यार्थी बहुत काम आते हैं।" उन्होंने बताया कि राजनयिक मिशनों के बाहर और भीतर के चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने अपने विद्यार्थी एजेंट तैनात कर रखे हैं ताकि वे "तिब्बत और फालुन गोंग जैसे विभिन्न बागी संगठनों में घुसपैठ कर सकें।"

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जोसिलीन छे, चीन और हांगकांग में रह चुके पूर्व वरिष्ठ राजनियक जो अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के फेलो और सिडनी यूनिवर्सिटी में विजि. टिंग प्रोफेसर हैं, कहते हैं: "यह साफ है कि यहां के राजनयिक मिशनों में तैनात चीनी अधिकारियों का बड़ा हिस्सा उनके नागरिकों पर अंकुश रखने के काम आता है। ◆

चीन की सोशल मीडिया से हुआ खुलासा, तिब्बत का हो रहा सैन्यीकरण

(एपक टाइम्स, 27 मार्च)।

तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला महल के पास ध्वजारोहण समारोह के दौर मार्च करते चीनी अद्ध सैन्य बल के जवान। फोटोः एपी, उमर अजीज

वे काफी आशा लेकर आते हैं, चीनी पर्यटकों को उम्मीद होती है कि तिब्बत में ताजा, साफ हवा मिलेगी, असाधारण पोटला महल देखने को मिलेगा, वहां के ऐसे खुशहाल मूल निवासी मिलेंगे जो खुद को अंधेरे युग से बाहर निकालने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कृतज्ञ दिखेंगे–लेकिन अचानक जब उनका तिब्बत के सैन्यीकरण जैसी सच्चाई से सामना होता है तो स्तब्ध रह जाते हैं और अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं।

एक बार जब वे कम्युनिस्ट पार्टी के भारी दुष्प्रचार वाले माहौल से दूर होते हैं तो भारी सुरक्षा के शिकंजे में कसे तिब्बत को देखकर उन्हें झटका लगता है। इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) की नई रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर खुलकर की गई गंभीर टिप्पणियों से यह असंतोष जाहिर होता है।

नई रिपोर्ट "हैज लाइफ आलवेज बीन लाइक दिस?" (क्या जीवन हमेशा ऐसा रहा है) उन हजारों मीडिया पोस्ट के आधार पर तैयार की गई है जिन्होंने सेंसर को धता बताते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के तिब्बत में 'स्थिरता बनाए रखने' के दावे के बारे में कई स्पष्ट खुलासे करते हैं।

ल्हासा से लौटा एक हक्का–बक्का पर्यटक भारी सैन्य मौजूदगी के बारे में लिखता हैः "जन सशस्त्र पुलिस, स्पेशल पुलिस, स्ना. इपर, सामान्य पुलिस, सेना के जवान ऐसे तैयार होकर खड़े हैं जैसे कोई युद्व शुरू होने वाला हो...क्या जीवन यहां हमेशा ही ऐसा ही रहा है?"

लिथांग नाम के एक छोटे से कस्बे का एक व्यक्ति लिखता है, "सड़कों पर हर तरह का दंगा नियंत्रण वाहन तैनात है, मुझे याद आ रहा है कि जब हम टीवी पर इराक की सड़कें देखते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखता है।"

एक और घबराया हुआ पाठक लिखता हैः "सशस्त्र जन पुलिस के जवान सड़कों पर गश्त करते हुए दिखते हैं...वे बड़ी बंदूकें हाथ में लिए रहते हैं...सड़कें विस्फोटक रोधी वाहनों और पुलिस कारों से भरी रहती हैं...हवा में दबाव है...क्या कुछ होने वाला है? मैं वास्तव में आतंकित हूं।" एक और अधीर पर्यटक कहता है, "मैं तो यहां से तत्काल वापस जा रहा हूं।"

मोबाइल फोन से तस्वीरें या अन्य 'संवेदनशील' के आदान–प्रदान के लिए जहां तिब्बतियों की जमकर पिटाई की जाती है, तो दूसरी तरफ, चीनी नागरिकों को पूरी छूट दी जाती है, हालांकि अक्सर उनसे भी फोटो को डीलीट करने को कहा जाता है या फोटो लेने से मना किया जाता है।

एक नाराज पर्यटक लिखता है, "यदि आप किसी अग्निशामक ट्रक का फोटो लेते हैं तो वे उसे भी मिटाने को कहते हैं। स्पेशल पुलिस वाहनों की फोटो भी नहीं ले सकते... इस समाज के साथ आखिर गलत क्या है?

इंटरनेट एवं मोबाइल फोन पर रोक, जगह–जगह सुरक्षा की चौकियां और बार–बार आईडी कार्ड मांगना पर्यटकों के लिए भारी पड़ता है। ऐसा ही एक पर्यटक लिखता हैः "हथियारों से लैस वाहन सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, इंटरनेट तक पहुंच पर पूरी तरह से रोक है, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं भेज सकते, खाना खाने के लिए बाहर जाने पर भी पुलिस वाले सवाल पूछते हैं, टीवी पर बहुत कुछ नहीं दिखता है, रात को दस बजे के बाद मोबाइल फोन सेवा भी नहीं चलती, मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि नहाऊं और जाकर सो जाऊं।"

हालांकि, बहुत से पर्यटक सेना की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं। एक पर्यटक ने लिखा है, "हमारे देश के सुरक्षा बलों ने जिस तरह की स्थिरता कायम की है वह वास्तव में काफी ताकतवर है, हर पांच कदम के बाद एक चौकी है और हर दस कदम पर एक संतरी दिख जाता है। यहां सुरक्षा तो किसी एयरपोर्ट से भी ज्यादा सख्त है, हर पांच मिनट के बाद कोई न कोई पुलिस वाहन गुजर जाता है, हर दस मिनट के बाद स्पेशल पुलिस का गश्ती दल गुजरता है, यहां तक कि हर आधे घंटे पर एक सैनिकों की टुकड़ी गुजरती है।" लेकिन एक दूसरा पर्यटक सवाल उठाता हैः "दूसरे लोगों से ज्यादा तो सशस्त्र जन पुलिस और नियमित पुलिस वालों की संख्या है। क्या यह जरूरी है? ◆

दलाई लामा की 13 दिवसीय घटनापूर्ण जापान यात्रा

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 19 अप्रैल)

परमपावन दलाई लामा के 16 अप्रैल को टोक्यो, जापान के सोतो समुदाय के सदस्यों से मुलाकात के दौरान सोतो बौद्ध परंपरा के उपाध्यक्ष एबे ईकाइ कैदियों द्वारा बनाए कंधे के दर्द को दूर करने वाला और पीठ रगड़ने वाला औजार दिखाते हुए। फोटोः तिब्बत प्रतिनिधि कार्यालय, जापान

दलाई लामा की जापान में 7 से 18 अप्रैल की यात्रा के दौरान उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रार्थनाओं का संचालन किया, सार्वजनिक व्याख्यान और धार्मिक उपदेश दिए, स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया, वैज्ञानिकों के साथ चर्चाएं कीं, बौद्ध व अन्य धर्मों के लोगों से मुलाकात की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने शिंतो धार्मिक संगठन, क्योटो के कोको वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, माइंड एवं लाइफ इंस्टीट्यूट और कोयासन मठ का दौरा किया। दलाई लामा का दौरा 7 अप्रैल से शुरू हुआ और इसी दिन उन्होंने सेंदई में उन लोगों के लिए एक विशेष प्रार्थना की जो मार्च 2011 में आए विनाशकारी सुनामी के दौरान मारे गए थे। इसके बाद वे "भयानक तबाही का सामना करने के लिए समझदारी और आत्मविश्वास की तलाश" विषय पर आयोजित एक सार्वजनिक व्याख्यान में शामिल हुए। उन्होंने कहा, "दुखद घटना को दृढ़ता और आशावाद में बदलकर एक बेहतर भविष्य तैयार कर आत्मविश्वास विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने 9 अप्रैल को ओसाका सिटी के सीफू गाकुएन ब्वॉयस स्कूल का दौरा किया और "युवा लोगों से क्या करने की उम्मीद की जा सकती है", विषय पर मिडल एवं हाई स्कूल के करीब 2,000 विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने हार्ट यानि हृदय सूत्र के संदर्भ से अपनी बात शुरू की जिसका पाठ उनके आने के तत्काल बाद कुछ बच्चों ने किया था। उन्होंने म्योदो–काई बौद्ध केंद्र का भी दौरा किया जहां उन्होंने एक संक्षिप्त पवीत्रीकरण समारोह भी संचालित किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इसी दिन बाद में सोतो जेन परंपरा के रिनान्जी मंदिर गए और भक्तों को "करुणा के द्वारा ताकत" विषय पर उपदेश दिया।

इसके बाद 11–12 अप्रैल को निर्वासित तिब्बत के आध्यात्मिक नेता ने "मैपिंग द माइंडः अ डायलॉग बिटवीन मॉडर्न साइंटिस्ट ऐंड बुद्धिस्ट साइंस" विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन क्योटो विश्वविद्यालय के कोको रिसर्च सेंटर और माइंड ऐंड लाइफ इंस्टीट्यूट ने

किया था। उन्होंने सुची–इन विश्वविद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने जापान के बौद्ध संप्रदाय के अनुयायिओं से भरे हॉल को संबोधित किया।

इसके बाद 13 से 14 अप्रैल में दलाई लामा ने जापान के शिंगोन बौद्ध संप्रदाय के कोयासन विश्वविद्यालय में धार्मिक उपदेश और सशक्तिकरण पर उपदेश दिया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 805 में कोबो दाइशी ने किया था। इस संप्रदाय को कभी इसोटेरिक बौद्ध संप्रदाय कहा जाता था। दलाई लामा ने वाइरोकाना–अभिसामबोधि पर सशक्तिकरण किया। जापानियों के अलावा इस शिक्षण में शामिल होने वालों में कोरिया, चीन, मंगोलिया के कुल एक हजार से ज्यादा लोग थे।

इस प्रवचन के बाद दलाई लामा ने 100 कोरियाई बौद्धों से अलग से मुलाकात की जिन्होंने यह उम्मीद जताई कि परमपावन एक दिन उनके देश की यात्रा करेंगे। परमपावन ने इस पर कहा कि वह पिछले कई साल से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह "कोरियाई सरकार की राजनीतिक एवं आर्थिक हितों और सोच–विचार पर निर्भर है।" उन्होंने इस बात पर पीड़ा जताई कि एक बौद्ध होने के बावजूद वह एक बौद्ध देश की यात्रा नहीं कर सकते।

इसके बाद 17 अप्रैल को भी टोक्यो के होटेल ओकुरा में दलाई लामा ने दिन भर धार्मिक उपदेश दिए। इस प्रवचन कार्यक्रम में करीब 1200 लोग उपस्थित थे जिनमें मंगोलिया, चीन, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से आए उनके भक्त शामिल थे। इसके पहले वह शहर में रहने वाले करीब 30 भारतीय कारोबारियों के एक समूह और चीनी लोगों के एक समूह से मिल चुके थे। उन्होंने सोतो जेन परंपरा के करीब 250 भिक्षुओं और समर्थकों से भी मुलाकात की। यह सामाजिक रूप से काफी सचेत संप्रदाय है जिसके सदस्य अपने बौद्ध धर्म के पालन के अलावा जेल में बंद लोगों के लिए पुरोहित का काम भी करते हैं।

इस बीच 15 अप्रैल को उन्होंने "हम अपना जीवन कैसे जिएं–21वीं सदी में धर्म एवं आचार" विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान को भी संबोधित किया और इसी दिन शिगोन बौद्ध पर्वतीय शहर में उनका तीन दिवसीय दौरा संपन्न हुआ। कोयासन विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस चर्चा में करीब 800 लोग आए थे।

दलाई लामा ने जापान की अपनी 13 दिवसीय यात्रा 18 अप्रैल को संपन्न की। इस दिन उन्होंने ताइवान, हांगकांग एवं मुख्य भूमि चीन के 100 से चीनियों, 50 मंगोलियाई लोगों और जापान में रहने वाले तिब्बती समुदाय के लोगों से मुलाकात की।

वर्ष 1967 में अपने पहले जापान दौरे के बाद से यह जापान में परमपावन की 20वीं यात्रा थी। दलाई लामा के टोक्यो स्थित प्रतिनिधि श्री ल्हाकपा सोको ने कहा कि उनकी इस यात्रा से जापानी लोगों, संगठनों और वहां के प्रमुख सरकारी विभागों में तिब्बत के बारे में एक अच्छी छवि बनाने में मदद मिलेगी और ताल्लुकात बेहतर होंगे। ◆

दलाई लामा के लिए प्रार्थना करने पर चीन ने तिब्बती भिक्षु को हिरासत में लिया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 23 अप्रैल)

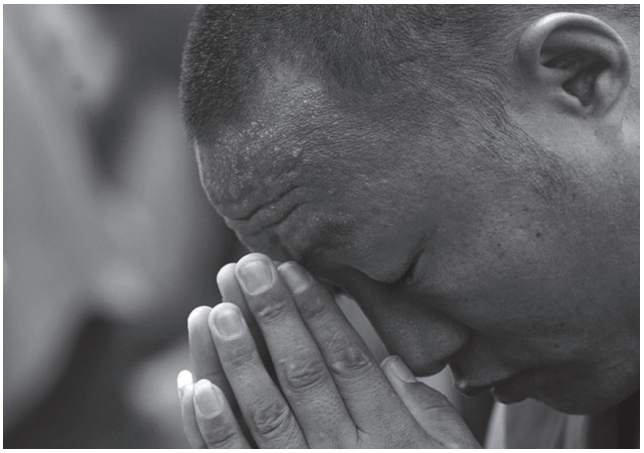

चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के चामदो प्रशासनिक क्षेत्र के पाशोए काउंटी में स्थित पाशोए मठ से एक धार्मिक शिक्षक और उनके कई शिष्य भिक्षुओं को मार्च के अंत में गिरफ्तार कर लिया है। इन भिक्षुओं को 'अपराध' बस यह था कि उन्होंने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के लिए प्रार्थना की थी और उनकी पूजा की थी। रेडियो फ्री एशिया ने 21 अप्रैल को एक स्थानीय सूत्र के हवाले से खबर दी है कि लोबसांग तेनजिन नाम के इस शिक्षक को छह या सात अन्य भिक्षुओं के साथ सुरक्षा बल उठा कर ले गए। यह गिरफ्तारी करने के लिए काउंटी पुलिस की एक टीम आई थी जो अचानक इसके लिए मठ में घुस गई। हालांकि, बाद में एक भिक्षु को रिहा कर दिया गया, लेकिन दूसरे भिक्षु कहां हैं, अभी इसका पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने यह आरोप लगाया है लोबसांग तेनजिन ने अन्य भिक्षुओं के साथ दलाई लामा के दीर्घायु होने के लिए एक विशेष प्रार्थना आयोजित की थी। भिक्षुओं पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वे उन्होंने भारत में इस साल 16 मार्च को दलाई लामा के दीर्घायु होने के लिए आयोजित विशेष प्रार्थना के लिए चंदा भेजा था। बताया जाता है कि पुलिस को लोबसांग तेनजिन के कमरे से दलाई लामा की तस्वीरें, उनके व्याख्यानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग और चंदा देने की कई रसीदें हासिल हुई हैं।

इसके पहले 4 मार्च को चीनी पुलिस ने पशोए मठ के एक और वरिष्ठ भिक्षु लोबसांग छोजोर को भी अपने साथ ले गई है और उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से कई प्रतिबंधित जानकारियों देश से बाहर भेजी हैं। ◆

एक दिन जरूर पूरा होगा हमारा सपनाः डॉ. लोबसांग सांगे

अनुराधा शर्मा, द डिप्लोमैट, 7 अप्रैल, 2014

(द डिप्लोमैट ने निर्वासित तिब्बतियों के प्रधानमंत्री से बातचीत की)

गत 26 अप्रैल को इस बात के तीन साल हो गए जब आपको चुनावों में ऐतिहासिक जीत मिली थी। दलाई लामा द्वारा अधिकार त्यागने के बाद आप तिब्बतियों के पहले राजनीतिक नेता बने। इसका अनुभव कैसा रहा?

पहला साल थोड़ा बेचैनी वाला था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि यह मेरा कर्म है और मैं बस सबसे बेहतर यही कर सकता हूं कि निर्वासन में और तिब्बत में रहने वाले तिब्बती जनता की आकांक्षाओं को पूरा करूं। करीब 400 साल पुरानी संस्था दलाई लामा में भी बदलाव आ रहा था। अचानक परमपावन ने बीड़ा राजनीतिक मुखिया को सौंपने का निर्णय लिया और यह दायित्व मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आ गयाः युवा, राजनीति के लिए नया और जिसके पास ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं थे। राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण को लेकर मैं चिंतित था जैसा कि बहुत से तिब्बती लोग थे। दूसरे वर्ष में यह चिंता कम हो गई, लेकिन मेरी व्यस्तता काफी बढ़ती गई और आज तक ऐसा ही है। सिक्किम के अलावा मै. ने भारत की सभी तिब्बती बस्तियों, सभी तिब्बती स्कूलों, 90 फीसदी मठों और 80 फीसदी वृद्ध आश्रमों का दौरा कर लिया है। उत्तर अमेरिका और यूरोप में मैंने तीन या चार स्थानों के अलावा बाकी सभी बड़ी तिब्बती बस्तियों का दौरा कर लिया है। मैं अब भी कठोर मेहनत कर रहा हूं और आगे भी ऐसा करने का इरादा रखता हूं। बाकी मैं तिब्बती जनता के सामूहिक कर्म पर छोड़ देता हूं।

क्या यह बिना किसी भौतिक सीमा वाले 'देश' को प्रबंधित करने जैसा है? इस बारे में चुनौतियां और अवसर क्या हैं?

सबसे बड़ी चुनौती यात्रा करने की है जो कि पांच महाद्वीपों की पूरी दुनिया में फैले तिब्बती जनसंख्या तक पहुंचने के लिए जरूरी है। हर बार यह काफी थकाऊ होता है– 13 या 14 दिनों में यूरोप के सात देशों की यात्रा और आठ दिनों में अमेरिका के सात राज्यों की यात्रा। आमतौर पर कार्यक्रम सुबह 8 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक होते हैं और इसके बाद रात्रिभोज तथा तिब्बती समुदाय के साथ औपचारिक संपर्क करते हैं। बिस्तर पर जाने तक अर्द्धरात्रि हो जाती है और अगली सुबह फिर जल्दी उठकर किसी और शहर या देश की यात्रा पर जाना पड़ता है। इसमें अच्छी बात यह होती है कि आप विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, विभिन्न संस्कृति और राजनीतिक वयवस्था से आपका साक्षात्कार होता है।

भारत से बैर मोल लिए बिना चीन से संपर्क करना क्या तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है? एक भारतीय अखबार में हाल में छपे एक

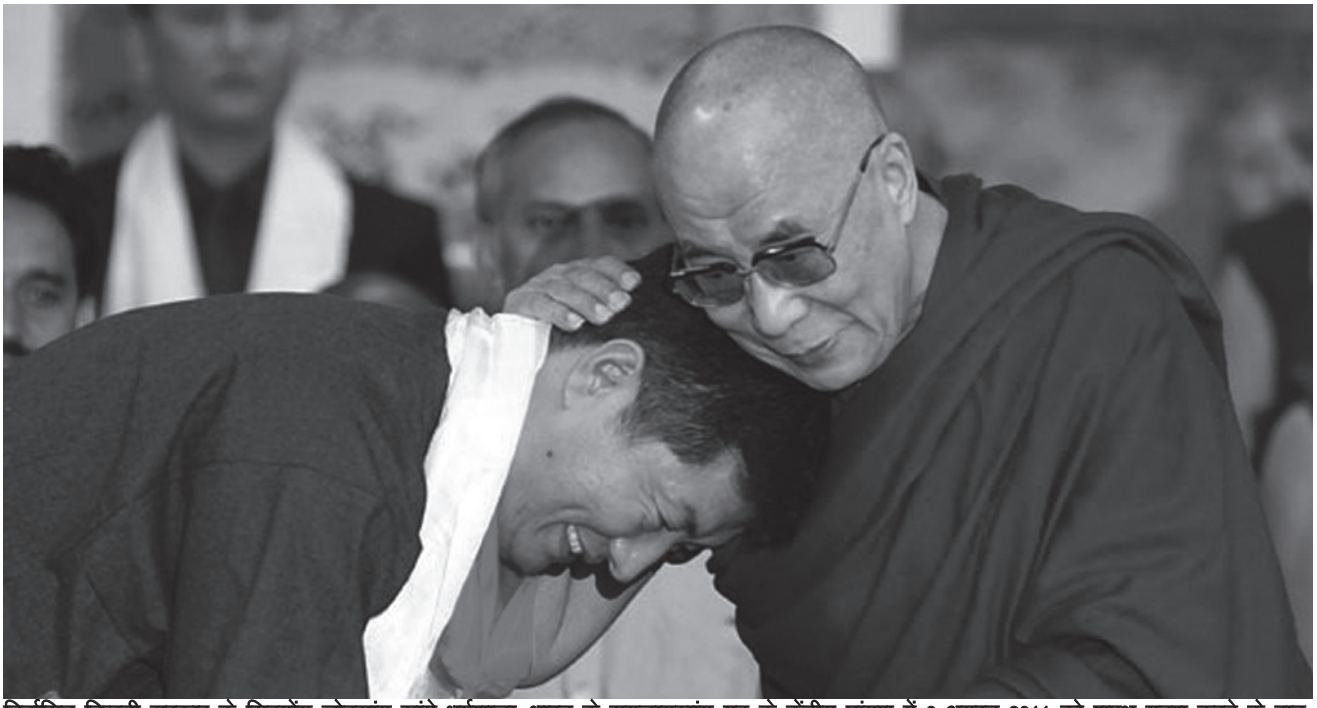

निर्वासित तिब्बती सरकार के सिक्योंग लोबसांग सांगे धर्मशाला, भारत के सुगलागखांग मठ के केंद्रीय प्रांगण में 8 अगस्त 2011 को शपथ ग्रहण करने के बाद परमपावन दलाई लामा से आशीर्वाद लेते हुए। फाइल फोटो

विचार लेख में आप पर आरोप लगाया गया है कि आप "चिंताजनक स्तर तक चीन की तरफ झुक रहे हैं" जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह की आलोचना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

मेरा जन्म भारत में हुआ है और मैंने कहीं और की तुलना में सबसे ज्याद साल यहीं गुजारे हैं। तिब्बतियों की सबसे ज्यादा मदद भारत ने की है, किसी भी और देश से ज्यादा। तिब्बती इसके लिए हमेशा भारत के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। मध्यम मार्ग नीति साफतौर से 70 के दशके के शुरुआती वर्षों से ही हमारी आधिकारिक नीति रही है। पिछली कशाग (मंत्रिमंडल) द्वारा 2008 में चीन सरकार को "तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता पर ज्ञापन" सौंपा गया था। "वाजिब स्वायत्तता" का मतलब यह है कि स्वायत्तता के उन अधिकारों को वाजिब तरीके से और अक्षरशः तथा मूल भावना के साथ लागू करना जो कि चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान और स्वायत्तता कानून में दिए गए हैं। मैं लगातार इस नीति के अनुरूप ही काम कर रहा हूं जो कि काफी समय से स्थापित है। न तो भारत सरकार और न ही भारत सरकार के किसी अधिकारी ने इस पर कभी आपत्ति जताई है। तिब्बत की स्वाधीनता की वकालत करने वाले बहुत से आलोचक ऐसा लगता है कि हमारे पक्ष को पसंद नहीं कर रहे और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हम तिब्बत की प्रभुसत्ता से समझौता कर रहे हैं। मैं भारत के बहुत से नेताओं और सत्ता में रहने वाले लोगों से मिला हूं और उन्होंने मेरा जिस तरह से स्वागत किया है और मेरे उनसे जिस तरह के रिश्ते हैं वह काफी सकारात्मक ही हैं। इसलिए आधिकारिक रूप से तो मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती। जहां तक आलोचकों की बात है, मैं क्या कह सकता हूं? लोग तमाम तरह की चीजें लिखते रहते हैं। मैं इस तरह के आरोपों को नजरअंदाज करता रहता हूं क्योंकि ये निराधार होते हैं। एक राजनीतिक नेता के रूप में आपको समय–समय पर आलोचना का शिकार होना ही पड़ता है।

लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत कुछ और कर सकता है?

हम भारत में मेहमान हैं और मांग करने की स्थिति में नहीं हैं। हां, यदि मौका मिले तो हम भारत से यह आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि चीन के साथ अपनी बातचीत में वह तिब्बत को मुख्य मसले के रूप में रखे। तिब्बत का मसला हल होना भारत के हित में है। भारत से हमारा अनुरोध है, जैसा कि हम अपने आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले किसी भी देश से करते हैं, कि वह तिब्बत का मसला शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए चीन पर वार्ता करने का दबाव बनाए।

लेकिन चीन लगातार आपको राजनीतिक प्रमुख के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता रहा है और उसने वार्ता को भी ठप कर दिया है।

हां, जनवरी 2010 से यह प्रक्रिया बाधित है, लेकिन तिब्बती पक्ष की अनिच्छा की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि चीन जमीनी स्तर पर कठोर नीतियां बनाए हुए है और नेतृत्व के स्तर पर उसने सख्त वाक चातुर्य का इस्तेमाल करता है। उन्होंने खुलेआम यह कहा है कि वे मुझसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि मुझसे बात करने का मतलब तिब्बती प्रशासन को मान्यता देना है। हालांकि, हमारे लिए प्रक्रिया दूसरे स्थान पर आता है और तत्व हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। हमने लगातार यह अनुरोध किया है कि परमपावन दलाई लामा के दूतों और उनके चीनी समकक्षों के बीच वार्ता को जारी रखा जाए।

इस साल मार्च में तिब्बत में तीन और आत्मदाह की घटनाएं हुई हैं, इससे आत्मदाह करने वालों की संख्या वर्ष 2009 से अब तक 129 तक पहुंच गई है। इन मसलों के समाधान के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?

हमने लगातार और स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया है कि तिब्बती समुदाय को आत्मदाह जैसे किसी भी प्रकार के चरम उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमारे अनुरोध के बावजूद आत्मदाह दुःखद रूप से जारी हैं, इसके लिए पूरी तरह से तिब्बत में होने वाले चीनी दमन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

अहिंसा के बुनियादी बौद्ध सिद्धांतों की मदद से इस तरह के हिंसक विरोध प्रदर्शन को किस तरह से शांत किया जा सकता है?

एक मनुष्य होने के नाते आत्मदाह हमें काफी दर्दनाक लगते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह से आत्मदाह करने वाले किसी भी तिब्बती ने एक भी चीनी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी चीनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। इसलिए यद्यपि यह काफी दर्दनाक तरह की मौत है, लेकिन आत्मदाह करने वालों ने यह ध्यान रखने की कोशिश की है कि किसी और को नुकसान न हो। यह किसी के लिए हिंसक कार्रवाई है, हां, लेकिन व्यापक अर्थ में देखें तो इसे सरसरी तौर पर "हिंसा" की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है।

क्या तिब्बत से शरणार्थी अब भी आ रहे हैं?

जी हां, बहुत से तिब्बती भारत में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए आते हैं और बहुत तो चीन की दमनकारी नीतियों की वजह से मजबूर होकर यहां आते हैं। हालांकि, अब वहां से आने वाले लोगों की संख्या घट गई है क्योंकि चीन सरकार ने नेपाली प्रशासन पर भारी दबाव बनाया है (तिब्बत से भागकर भारत आने वाले शरणार्थियों को नेपाल सीमा से ही होकर आना पड़ता है) और सीम. ावर्ती इलाकों को अच्छी तरह से सील कर दिया गया है।

आप कभी भी तिब्बत नहीं गए हैं। आपको अपने मां–बाप से तिब्बत की किस तरह की यादें मिली हैं?

मेरा जन्म दार्जिलिंग की एक तिब्बती बस्ती में हुआ था, जहां मेरे मां–बाप शरणार्थी थे। मेरे पिता लिथांग के भिक्षु थे और मां चामदो की रहने वाली थीं, दोनों में अक्सर यह बहस होती रहती थी कि किसका गांव ज्यादा खूबसूरत है। मुझे खूबसूरत भूमि, साफ जलधाराओं, पेडों, फूलों और खेतों की कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन मैं सोचता था कि यह खूबसूरती का अंश सिर्फ गर्मियों में ही सच होता होगा (हंसते हैं)।

हाल में मैं अरुणाचल प्रदेश गया था (तिब्बत से सटा पूर्वोत्तर का भारतीय राज्य) और मैंने तवांग, तुतिंग तथा गेलिंग इलाके का दौरा किया। मैं मैकमोहन रेखा के करीब था और मैं कल्पना कर रहा था इस पार के भारत के तरह ही उस पार तिब्बत कैसा होगा। जुलाई 2012 में लद्दाख के दौरे के समय मैं दूसरे तरफ तिब्बत को देख सकता था–सूखा, सूखे पहाड़ जिन पर वनस्पतियां बहुत कम दिख रही थीं। अब मैं सिक्किम जाने की योजना बना रहे हूं और इस बार फिर दूसरी तरफ तिब्बत की ओर नजर डालूंगा। मौजूदा परिस्थितियों में तिब्बत के ज्यादा से ज्यादा करीब होने की मैं इसी तरह से कोशिश कर रहा हूं।

क्या आपको यह उम्मीद है कि आपके जीवन में तिब्बत को हासिल करना संभव होगा?

हां, इसीलिए मैंने अमेरिका छोड़ा है और इसके लिए काम करने यहां आया हूं। मेरी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा परमपावन दलाई लामा और मेरे मां–बाप के पदचिह्नों पर चलने जैसा है। मैंने बॉमडिला गांव में अपने स्वर्गीय पिता को याद किया जहां सीमा पार करने के बाद वह पहली बार ठहरे थे। तुतिंग में मुझे अपनी मां की याद आई जहां वह दार्जिलिंग जाने से पहले कुछ समय के लिए ठहरी थीं। दार्जिलिंग में मेरे मां–बाप मिले थे और साथ रहना शुरू किया था। दोनों ने परमपावन का अनुसरण किया था जो 55 साल पहले सीमा पार कर तवांग होते हुए भारत में आए थे। जब वे सीमा पार कर आए तो उनके पास ज्यादा सामान नहीं था क्योंकि वे फिर वापस जाने के इरादे के साथ आए थे। घर वापस जाने का उनका यह इंतजार 55 साल तक का हो चुका है और 2004 में मेरे पिता का निधन हो गया, इस सपने के पूरा हुए बिना। इसी तरह की कहानी निवार्सन में रहने वाले और तिब्बत के भीतर रहने वाले हजारों तिब्बतियों की है। इन सबकी वजह से मैं अपने उद्देश्य के प्रति और दृढ़ हुआ। उनके सपने को पूरा करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यह मेरी पहचान और गरिमा पाने की तलाश है। एक दिन हम इसे हासिल कर लेंगे। अतीत में आप तिब्बती युवा कांग्रेस और स्टुडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत के सदस्य रह चुके हैं, दोनों संगठन रंगजेन यानि तिब्बत के लिए पूरी स्वाधीनता का समर्थन करते हैं। अब आप केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख के रूप में मध्यम मार्ग के पक्के समर्थक हैं।

मैं तिब्बत के लिए अब भी उसी तरह का जुनून रखता हूं जैसा पहले था। हालांकि, एक समय के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि हमारे बुजुर्गों के लिए मध्यम मार्ग का चुनाव करना समझदारी और यथार्थवादी था। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हैः चीन की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता बनी रहेगी और तिब्बत को भी वाजिब स्वायत्तता मिलेगी।

दलाई लामा का लक्ष्य धर्म से राजनीति को अलग करना था। क्या ऐसा हो पाया है?

काफी हद तक। यह अब भी बदलाव के द्वारा जारी है, लेकिन संस्थागत रूप से और संवैधानिक रूप से और दिन–प्रति–दिन आधार पर देखें तो साफ तौर से अलगाव हो चुका है। परमपावन अब भी तिब्बतियों के बीच सबसे लोकप्रिय और सबसे पूज्यनीय व्यक्ति बने हुए हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने उदारता दिखाते हुए अपने राजनीतिक अधिकार त्याग दिए हैं, इसलिए सचेत रहकर ऐसा रवैया अपनाते हैं जिससे इस अलगाव का बने रहना सुनिश्चित हो सके।

क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति धार्मिक रहे बिना निर्वासित तिब्बत सरकार में मंत्री बन सके?

जी हां।

क्या आप किसी निर्णय को लागू करने से पहले उस पर परमपावन से राय लेते हैं?

आधिकारिक रूप से यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन उनके पास व्यापक अनुभव है और किसी भी मसले पर उनकी राय लेना बहुत अच्छी बात है, यद्यपि वह जानबूझ कर कोई औपचारिक निर्देश नहीं देते। एक बार उन्होंने मजाक में कहा था, अब मैं लोगों को चुना हुआ प्रतिनिधि हूं इसलिए अब मेरी खुद उनके (परमपावन) सहित अन्य सभी लोग आलोचना कर सकते हैं। (हंसते हैं)। मैं अंतिम चीज चाहता हूं, उनके द्वारा आलोचना। ◆

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मीडिया किस तरह से काम करती हैः एक खुलासा

(काई चेंग, पीपल्स डेली के पूर्व पत्रकार, 27 मार्च, 2014)

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के प्रोपेगंडा अखबार पीपल्स डेली के पूर्व पत्रकार के निंदात्मक खुलासे से यह पता चलता है कि इस अखबार का उद्देश्य पार्टी के हितों और छवि को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है और इसके लिए यह खबरों से छेड़छाड़ करता है। अपने को पीपल्स डेली का पूर्व रिपोर्टर बताने वाले चेंग काई का यह लेख चेंग मिंग पत्रिका के मार्च संस्करण में छपा है। चीनी भाषा से अनुवादित आलेख का संपादित अंश यहां पेश हैः

वैसे तो पीपल्स डेली को एक अखबार बताया जाता है, लेकिन इसमें खबरें नहीं होतीं। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के लिए एक प्रोपेगंडा टूल है। इसमें खबरों से छेड़छाड़ किया जाता है और सच्ची घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं की जाती।

सीसीपी अक्सर लाल रंग के शीर्षक वाला एक "रेड हेड" दस्तावेज सभी निचले स्तर के पार्टी और सरकारी कार्यालयों को भेजती है। इसमें यह निर्देश होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पीपल्स डेली असल में इस "रेड हेड" का ही विस्तारित संस्करण है क्योंकि यह पार्टी में निचले स्तर तक पहुंच जाता है।

मैं सीसीपी के पीपल्स डेली की समाचार टीम का हिस्सा था और मुझे यह बताया गया कि पार्टी के अखबार का ध्येय पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को बढ़ावा देना तथा पार्टी के हितों एवं छवि की रक्षा करना है। मुझसे कभी यह नहीं कहा गया कि कोई खबर दो या सूचना का प्रसार करो।

जनता के साथ धोखा

पीपल्स डेली वह काम करती है जो "रेड हेड" नहीं कर पाती और यह काम है जनता को धोखा देना। पीपल्स डेली के पूर्व अध्यक्ष हू जिवेई ने पीपल्स डेली के बारे में कहा, "इसमें बस अखबार की प्रकाशन तिथि ही सत्य होती है, बाकी सब नकली होता है।"

पीपल्स डेली पढ़ने वाले चीनी पाठकों को खबरों को उलट कर समझना चाहिएः यदि अखबार किसी चीज को बहुत बढ़िया बता रहे हैं तो यह निश्चित रूप से भयावह होगा, यदि यह कह रहा है कि भविष्य उज्ज्वल है तो मान लीजिए यह निराशाजनक है। हर दिन या हर कुछ दिनों के बाद पार्टी के अखबार के संपादकों और पत्रकारों को यह बताया जाता है कि नेता क्या चाहते हैं। इसके बाद वे ऐसे विषयों की तलाश करते हैं जिनके माध्यम से नेताओं का संदेश जनता में पहुंचाया जा सके।

संपादकों से यह भी कहा जाता है कि वे सर्वोच्च पार्टी नेताओं की आकांक्षा के अनुसार ही चलें। तथाकथित आम सहमति का मतलब यह है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के अनुरूप बने रहना है। पीपल्स डेली से तो खासतौर से यह उम्मीद की जाती है कि शीर्ष नेताओं के विचारों के साथ बिल्कुल सामंजस्य बना कर चले।

मैंने हाल में ही पीपल्स डेली पढ़ा और मैंने अक्सर देखा कि शी जिनपिंग की ऐसी गतिविधियों को भी फ्रंट पेज पर जगह दी गई है, जिनका खबरों के लिहाज से कोई महत्व नहीं था। पीपल्स डेली के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के किसी विदेश नेता से हाथ मिलाती हुई तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण खबर कुछ होती ही नहीं।

प्रोपेगंडा मशीन

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी असल में चीन में शासन करने के लिए प्रोपेगंडा (दुष्प्रचार) पर ही निर्भर है और पीपल्स डेली इसका सबसे बेहतरीन प्रोपेगंडा मशीन है। चीन की विभिन्न मीडिया में से केवल पीपल्स डेली के अध्यक्ष को सीसीपी की पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठकों में शामिल होने का अधिकार है।

पीपल डेली में प्रकाशित कोई भी टिप्पणी पार्टी के केंद्रीय अधिकारियों के विचारों को पेश करती है। सभी संपादकीय और टिप्पणियों को छापने से पहले स्थायी समिति के सदस्यों या पार्टी के महासचिव से मंजूर कराना पड़ता है।

पीपल्स डेली जिस फंड के सहारे चलता है उसे सीसीपी का केंद्रीय प्रशासन ही मंजूर करता है। पार्टी के रेगुलेशन और प्रशासनिक आदेश के बिना इस अखबार की हर दिन 25 लाख से 30 लाख प्रतियां बिकना संभव नहीं है।

सरकारी विभाग भी इस अखबार की ग्राहकी लेने का महत्व समझते हैं–पीपल्स डेली पढ़ना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे यह पता चलता है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सोच और इच्छा क्या है और इस आधार पर ही गलतियों से बचा जा सकता है।

आंतरिक संदर्भ दस्तावेज

पीपल्स डेली के आधे रिपोर्टरों का तो एक साझा काम हैः पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी की तरफ से तथाकथित "आंतरिक संदर्भ" तैयार करना। इससे पीपल्स डेली के पत्रकारों को पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी के बारे में सीधे सूचना हासिल करने की सुविधा मिलती है।

पीपल्स डेली हर दिन दो बार आंतरिक संदर्भ जारी करती है यह सीधे पोलित ब्यूरो के सदस्यों की टेबल तक पहुंचता है। "अति गोपनीय" के रूप में वर्गीकृत सूचनाएं सीधे पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्यों तक भेजी जाती हैं।

आंतरिक संदर्भ में यह ताकत होती है कि किसी अधिकारी के करियर या किसी क्षेत्र के प्रशासन पर असर डाल सके। इसलिए सभी स्तर के सरकारी अधिकारी पीपल्स डेली के पत्रकारों को बहुत सम्मान देते हैं। जब मैं पीपल्स डेली में शेनझेन स्पेशल इकनॉमिक जोन के संवाददाता के रूप में काम करता था तो मैंने एक आंतरिक संदर्भ लिखा और यह बताया कि शेनझेन एयरपोर्ट की जो जगह चुनी गई है वह उपयुक्त नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर शेनझेन एयरपोर्ट को बाइशिझू (शेनझेन यूनिवर्सिटी के बगल में स्थित पक्षी विहार) से हटा कर हॉनगटियन कर दिया गया, जहां आज यह एयरपोर्ट स्थित है।

अब तो पीपल्स डेली के ज्यादातर पत्रकार सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों से घूस लेते हैं। किसी सरकारी अधिकारी या कारोबारी की तारीफ में खबर प्रकाशित करने पर हजारों युआन का घूस मिल जाता है। इसके बदले में अधिकारी और कारोबारी को काफी फायदा होता है यदि पीपल्स डेली के आंतरिक संदर्भ में उसकी तारीफ कर दी जाती है तो।

नहीं मिलता प्रमोशन

कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व वाले अखबारों के संपादकों को पार्टी कैडर माना जाता है। पीपल्स डेली के अध्यक्ष और संपादक अक्सर प्रांतीय स्तर के पार्टी सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रियों या वरिष्ठ सेना अधिकारियों में से चुने जाते हैं। पत्रकारिता के पृष्ठभूमि वाले लोगों को तब ही शीर्ष पद दिया जाता है यदि वे उन्हें इससे कोई गुरेज न हो कि पार्टी उनका चरित्र हनन कर दे। देंग तुओ इसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्थिति से आजिज आकर आखिर आत्महत्या कर ली थी। पीपल्स डेली के मौजूदा मुख्य संपादक कभी रिपोर्टिंग में मेरे सहयोगी हुआ करते थे। उस समय वह हेबेई प्रांत में संवाददाता थे और उन्होंने अपनी छवि आज्ञापालक तथा अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति की बनाई। अब वह मुख्य संपादक हैं। हालांकि, वह काले को सफेद कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के सार्वभौमिक मूल्यों के विरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों की वकालत करने में लगे हैं। ◆

यूरोपीय संघ को मानवाधिकारों और तिब्बत के मसले पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देनी चाहिए चुनौती

(ईयूआरएक्टिव डॉट कॉम, 26 मार्च 2014)

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह एक ऐतिहासिक गलती होगी यदि यूरोपीय संघ के नेता लगातार मानवाधिकारों के मसले पर चीन से बात करने से कतराते हैं। छह राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों ने एक संयुक्त लेख में यह बात कही है। यह लेख बेल्जियम के मध्य–दक्षिणपंथी सांसद जॉर्जेस डैलेमागने, फ्रांस के ग्रीन पार्टी के सीनेटर एंड्रे गैटोलिन, यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति के अध्यक्ष हेनरी मलोसी, यूरोपीय संसद के जर्मन सदस्य और तिब्बत इंटरग्रुप थॉमस मान, इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत के अध्यक्ष माटेवो मेकाक्की और नीदरलैंड के समाजवादी सांसद हैरी वान बोमेल शामिल हैं। लेख इस प्रकार हैः

शी जिनपिंग का चीन के नेता के रूप में यूरोप का पहला दौरा करीब एक साल तक व्यापार पर बने रहे तनाव के बाद महत्वपूर्ण समय में हो रहा है, आंतरिक दबाव बढ़ रहा है और चीन एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति शी के फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड की यात्रा करने की उम्मीद है। चीन के साथ संपर्क रखना और उसके साथ व्यापारिक रिश्ते कायम करना यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि यूरोप के नेता चीन के साथ बातचीत में अन्य सामरिक मसलों को नजरअंदाज करते हैं तो यह ऐतिहासिक गलती होगी। चीन की जबर्दस्त आर्थिक तरक्की की तुलना में वहां कानून के शासन, मानवाधिकारों, लोकतंत्र और पर्यावरण को सम्मान नहीं हो पाया है। इसके विपरीत हम यह भी देख रहे हैं कि मुख्यभूमि चीन, तिब्बत और शीक्यांग में सख्ती और व्यवस्थित दमन बढ़ रहा है।

हाल में चीन के कानूनी विद्वान शू झियों को, जिन्होंने चीन के संविधान को और पुख्ता बनाने का समर्थन किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की वजह से चार साल तक के कैद की सजा दी गई, शीर्ष उइगर प्रोफेसर इलहाल तोहती को उनके घर से उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तिब्बत में हाल में खेनपो कार्तसे नाम के एक सम्मानित मठाध्यक्ष की हाल में गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया और वहां आत्मदाह की दुखद घटनाएं अब भी जारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर देखें, तो बीजिंग ने उन सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों को बर्बाद कर दिया या उसका राजनीतिकरण कर दिया

चीन जनवादी गणतंत्र के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 मार्च से 1 अप्रैल, 2014 तक ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ के दौरे पर थे। इस दौरान शी जिनपिंग के साथ दिख रहे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हर्मन वान रोमपुई और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोस मैन्युएल बारोसो।

जहां उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड को चुनौती दी गई। इसके साथ ही भारतीय सीमा और पूर्वी चीन सागर में चीनी सैन्य बलों की एकतरफा कार्रवाई से यह समझा जा सकता है कि किसी अधिनायकवादी तंत्र द्वारा संचालित वैश्विक ताकत के आर्थिक एवं सैन्य उभार से किस तरह का जोखिम आ सकता है। ऐसे देश से रिश्ते बनाने में जिसके नियम और मूल्य हमारे लोकतंत्रों के विपरीत हो एक एकीकृत यूरोपीय नीति रखना इस समय बहुत जरूरी है। यूरोपीय नागरिक अपने इतिहास से यह जानते हैं कि दूसरे उभरते दमनकारी सरकारों की आक्रामक नीतियों के आगे आत्मसमर्पण करने पर क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चीन के साथ हमारे रिश्तों में जो कुछ दांव पर लगा हुआ है वह किसी व्यापारिक सौदे या उनके बाजार पहुंच से आगे की चीज है और इससे उस दुनिया की प्रकृति या भविष्य तय होता है जिसमें हम रहना चाहते हैं।

इन सबका विकल्प मौजूद हैः कानून का शासन और बुनियादी आज़ादी का सम्मान शांति बनाए रखने और सामाजिक प्रगति की दीर्घकालिक गारंटी साबित हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी से मिलने वाले यूरोपीय संघ के नेताओं को इस महत्वपूर्ण अवसर का इस्तेमाल यह साफ संदेश देने में करना चाहिए किः

यूरोपीय संघ–चीन निवेश समझौते और उसके बाद मुक्त व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत को चीन में कानून एवं मानवाधिकार में सुधार से जोड़ा जाए जैसा कि यूरोपीय सांसदों ने सिफारिश की है। समझौतों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने की बाध्यता को भी शामिल करना चाहिए।

यूरोपीय संघ द्वारा हथियारों की आपूर्ति पर लगे रोक को खत्म करने के चीन के अनुरोध को तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक वहां के सैनिकों की तैनाती नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के दमन के लिए की जाती है।

चीन के बारे में यूरोपीय एकता से यूरोपीय संघ का वजन इन दोनों बातों के लिए बढ़ेगा, कि मजबूत व्यापारिक रिश्तों में योगदान कर सकें और चीन को एक ज्यादा जिम्मेदार वैश्विक देश बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। दूसरे की कीमत पर पहली बात पर ध्यान केंद्रित करने से चीनी नेताओं को चर्चाओं में प्रभुत्व जमाने का मौका मिलता है और चीन द्वारा अपनी बात पर दृढ़ रहने से यूरोप के सामरिक हित नजरअंदाज हो जाते हैं।

हम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लिउ शियाबाओ, जिन्हें चीन ने जेल में डाल रखा है और उनकी पत्नी के लिउ शिया के प्रति एकजुटता के साथ खड़े हैं। उनकी पत्नी को भी नजरबंद रखा गया है।

हम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा का भी स्वागत करते हैं जो इस वसंत में लातविया, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी और इटली का दौरा करने वाले हैं। वह तिब्बत में शांति और सुरक्षा पर अपनी दृष्टि को पेश करेंगे इसलिए चीनी राजनयिक यूरोपीय देशों का दौरा कर उनके दौरे को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि यूरोपीय नेता उनसे न मिलें। लेकिन चीन की इस मांग के आगे झुकना एक और दुखद गलती होगी, न सिर्फ तिब्बत के भविष्य के लिए बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए भी। यूरोपीय देशों के नेताओं को यह तय करना होगा, चीनी नेताओं को नहीं, कि दलाई दलामा के साथ उन्हें किस तरह का रिश्ता रखना है।

यूरोपीय नेताओं को चीनी राष्ट्रपति शी से यह कहना चाहिए कि वह तिब्बत के लिए वार्ता के द्वारा कोई स्वीकार्य राजनीतिक हल निकालें और उन दमनकारी नीतियों को वापस लें जिनसे तिब्बती जनता में अलगाव और असंतोष पैदा होता है।

इसके अलावा उन्हें दलाई लामा से भी बातचीत करनी चाहिए जो शांति और लोकतंत्र के अहिंसक समर्थक हैं और तिब्बती तथा चीनी जनता के बीच एकता एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

यूरोपीय यूनियन यदि एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के साथ अलग व्यवहार करता है तो यह न केवल एक गलती होगी, बल्कि उन मूल्यों को त्यागना भी होगा जिनके आधार पर हमने मुक्त समाज का निर्माण किया है, यह यूरोप द्वारा किसी भी व्यापारिक सौदे के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी कीमत होगी। ◆

चीन की तिब्बत समस्याः एक मिथक पर कैसे पाएं जीत

अपने अशांत जनसंख्या और दुनिया की राय से निपटने में चीन आधुनिक शासन कला की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है।

स्टीफन हाल्पर और लीजली ब्राउन : हाल्पर लॉस एंजिलिस टाइम्स, 10 अप्रैल, 2014

बीजिंग के पास सामना करने के लिए मसलों की कमी नहीं है। वहां दक्षिण चीन सागर, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, सुस्त होती अर्थव्यवस्था है और पार्टी एवं सेना के घटकों के बीच कई तरह के विवाद हैं। हालांकि, चीनी अधिकारी आधुनिक शासन कला की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैंः कि आखिर किसी मिथक पर विजय कैसे पाई जाए।

तिब्बत के मिथकीय आकर्षण को खत्म करने के चीन के प्रयास के बावजूद यह शांग्री–ला के रूप में दुनिया की कल्पना में मजबूती से बैठा हुआ है। कभी स्वतंत्र देश रहा तिब्बत हिमालय के सटे एक विशाल ऊंचे पठार पर स्थित है और रहस्य, आकांक्षा, आध्यात्मिकता और संभाव्यता का वैश्विक प्रतीक है। दुनिया भर के नेता इसके निर्वासित आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा से मिलने को अब भी इच्छुक रहते हैं और वह जहां भी जाते हैं ऑडिटोरियम लोगों से भर जाता है। दुनिया में कहीं के लोग भी जब किसी पवित्र स्थली की तस्वीर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में तिब्बत ही आता है।

हालांकि, माओ–त्से–तुंग ने जब 1950 में तिब्बत पर चढ़ाई के लिए जन मुक्ति सेना भेजी तो उनके दिमाग में यह नहीं था। वह यह जानते थे कि उनके इस कदम से जटिल राजनीतिक एवं सैन्य चुनौतियां पैदा होंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ी सी सफलता से भी वह इस छोटे से देश को चीन के अधीन कर लेंगे, इसके पहले कि पश्चिमी देश तिब्बत के किसी तरह के प्रतिरोध का समर्थन करें।

आज इस हमले के करीब छह दशक बीत जाने के बाद और चीन द्वारा सालों से इस इलाके में चीनी नस्ल के लोगों को बसाने की कोशिशों के बाद भी तिब्बत पर विजय नहीं पाई जा सकी है। आमतौर पर राजनयिक विरोध से बचने की चतुराई रखने वाले चीन को तिब्बत में अपनी नीतियों के बारे में दुनिया भर की आलोचना सहनी पड़ रही है, यह अलग बात है कि इन नीतियों को वापस लेने की दिशा में प्रगति बहुत कम हो पाई है। जनमुक्ति सेना के कब्जे में तिब्बत पिस रहा है और दुनिया देख रही है कि चीनी सैनिक ल्हासा की सड़कों पर अग्निशन यंत्रों के साथ गश्त कर रहे हैं, चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले तिब्बतियो की आग बुझाने को तैयार।

बीजिंग में टूअर ऑपरेटर तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों का टिकट बेचते हैं, हालांकि वे एक मनोरंजन पार्क का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए जोखांग मंदिर में अब भी तीर्थयात्री बहुत दूर–दूर से हर सुबह मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने और परिक्रमा करने आते हैं। हालांकि, चीनी पर्यटक भी आते हैं, तिब्बत के टुअर पर उनके हर स्टॉप पर टिकट पर एक मुहर लगाया जाता है और वे प्राचीन रीति–रिवाजों को बहुत उपहास की नजरों से देखते हैं। इस बढ़ते पर्यटन उद्योग से लगातार तिब्बत के गहर सामाजिक–धार्मिक ताने–बाने को नुकसान हो रहा है, हालांकि अभी वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

चीन ने तिब्बत में अरबों डॉलर धन झोंके हैं ताकि तिब्बती संस्कृति में व्यवस्थित बदलाव से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वहां दलाई के प्रति श्रद्धा का खुलेआम प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर रोक है, लेकिन सड़कों और रेल सेवाओं में सुधार हुआ है।

गर्म जल अब हर कहीं उपलब्ध है और बड़े शहरों में मकान एवं स्कूल आधुनिक हो गए हैं, जहां ज्यादातर हान चीनी लोग रहते हैं। स्वाभाविक रूप से इन तीव्र बदलावों की वजह से तिब्बती समाज के भीतर तनाव बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग चीन द्वारा उपलब्ध "अवसरों" का फायदा उठाना चाहते हैं–बिजनेस लाइसेंस, नगर निगमों में नौकरियां आदि–जबकि समूचे तिब्बत के गांवों में रहने वाले तिब्बती अपनी विरासत में होने वाले क्षरण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

पिछली आधी सदी से हान संस्कृति के खिलाफ तिब्बतियों के प्रतिरोध के साथ ही पश्चिम में परंपरागत तिब्बत के प्रति गहरी सहानुभूति देखी गई है। इससे चीन की तिब्बत समस्या को एक नया और अलग आयाम मिला है।

तिब्बती मिथक के साथ पश्चिमी देशों की आसक्ति ने तिब्बतियों को एक विशिष्ट "नरम शक्ति" को भोगने में सक्षम बनाया है–नैतिक निंदा की शक्ति–जिस पर न तो चीन कोई नियंत्रण कर सकता है और न ही सुधार कर सकता है। यह एक ऐसी मुलायम शक्ति है जिसने चीनी समाज और शासन को चलाने वाले मूल्यों के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं।

तिब्बती संस्कृति को चीन द्वारा नष्ट करने की वैश्विक आलोचना तो अब सार्वभामिक हो गई है। यहां तक कि वर्ष 2008 के ओलंपिक के समय ल्हासा में हुए दंगों और भयावह आत्मदाह के बारे में, जो कि 2009 से अब तक 126 तक पहुंच गए हैं, अक्सर अखबारों के पहले पेज पर खबरें छापी जाती हैं। इन खबरों में हमेशा चीन द्वारा तिब्बत के कब्जे को क्रूर और दमन. कारी बताया जाता है। यह खासकर उस समय समस्या बन जाती है जब चीनी नेतृत्व दुनिया को अपने प्रगतिशील मूल्यों, सुधारों और कानून के बदलावों के बारे में बताने की कोशिश करता है। चीन विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और विश्व व्यापार संगठन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका चाहता है, लेकिन तिब्बत में शासन के नैतिक धब्बे की वजह से उसकी संभावनओं पर ग्रहण लग जाता है।

मौजूदा नीतियों से न तो चीन को फायदा हो रहा है और न ही तिब्बत को, इसलिए अब समय आ गया है कि बीजिंग के नेता तिब्बत के बारे में नए सिरे से विचार करें। चीन का "एक देश, दो व्यवस्था" मॉडल वैसे तो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन यह हांगकांग में कारगर है। आखिर इसका संस्करण तिब्बत में क्यों नहीं लागू किया जा सकता, तिब्बतियों को अपने घरेलू शासन पर ज्यादा नियंत्रण हो और धर्म के मामले में भी ज्यादा आज़ादी दी जाए? इस इलाके पर चीन की प्रभुसत्ता बनी रह सकती है, खासकर प्रतिरक्षा और विदेश नीति लागू रह सकती है और हान चीनी तथा तिब्बती दोनों तरह के लोगों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय तथा विवाद समाधान तंत्र बनाए जा सकते हैं। यहां तक कि दलाई लामा भी जो तिब्बत के लिए ज्यादा स्थानीय स्वायत्तता चाहते हैं, तिब्बत की पूरी स्वाधीनता की मांग नहीं कर रहे।

ऐसे विकल्प पर चीन को इसलिए भी विचार करना चाहिए क्योंकि मौजूदा दलाई लामा के निधन होने के बाद (वह अब 78 साल के हो चुके हैं) तिब्बती नेतृत्व ज्यादा उग्र और टकराव करने वाला हो सकता है। ऐसा यदि होता है तो चीन की नीति और दमनकारी हो सकती ही जिससे तिब्बत की नरम शक्ति और बढ़ेगी, तथा चीन के प्रति वैश्विक राय और नकारात्मक हो सकती है। इसके विकल्प में यदि चीन तिब्बत को ज्यादा स्वायत्तता देता है तो एक कठिन समस्या के तार्किक समाधान निकालने के लिए चीन की तारीफ की जा सकती है। ◆

(स्टीफन हाल्पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विभाग में अमेरिकी अध्ययन के निदेषक हैं। लीजली ब्राउन हाल्पर कैम्ब्रिज के कॉरपस क्रिस्टी कॉलेज में रिसर्च एसोसिएट हैं)

एक टूट चुका आदमीः तिब्बत के प्रमुख कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का निधन

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 31 मार्च, 2014)

फुंत्सो वांगये

तिब्बत में 1940 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले फुंत्सो वांगये का गत 30 मार्च को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वांगये ने बाद में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय कर दिया ताकि उसकी मदद से तिब्बत में काफी पिछड़े रजानीतिक व्यवस्था एवं समाज में बदलाव लाया जा सके। लेकिन उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह यह थी कि तिब्बत में सुधार के लिए तिब्बती पहचान को बनाए रखने का उनका जो विचार था वह बीजिंग के पार्टी नेतृत्व की एकीकरण, विलोपन और अधीन बनाने की नीति से मेल नहीं खाता था। चीन ने जब तिब्बत को पूरी तरह से हड़प लिया और दलाई लामा को भाग कर भारत जाना पड़ा, उसके एक साल पहले 1958 में ही वांगये को जेल में डाल दिया गया।

हालांकि, दशकों तक उपेक्षित रहे और सताए जाने के बावजूद, जबकि चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में रखा था और वहां की संस्कृति का व्यवस्थित तरीके से विनाश किया जा रहा था तथा वहां के लोगों पर भारी अत्याचार किया जा रहा था, वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक चीनी नेतृत्व को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करते रहे कि कि वह तिब्बत पर अपनी नीतियों में बदलाव लाएं और दलाई लामा से बात करें।

वर्ष 1922 में बतांग तिब्बती काउंटी में जन्मे फुनवांग (उनका एक नाम यह भी है) ने 1951 में इस सुदूर हिमालयी देश में चीन की जनमुक्ति सेना के हमले में उनका साथ दिया था और चीनी नेता माओ–त्से तुंग तथा चाउ एन लाई की 1954 में दलाई लामा से बातचीत में अनुवादक की भूमिका निभाई थी। हालांकि, 1958 में उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया, इसके बावजूद वह 1978 में पुनर्वास किए जाने से पहले 18 साल तक काल कोठरी में बंद रखे गए।

उन्होंने कुख्यात क्विंगछेन जेल में गुजारे अपने कैद के वर्षों को "वर्णन से परे" बताया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बहुत खराब दौर में, जिसे चीन अब सांस्कृतिक क्रांति (1966–76) का "अराजक" दशक बताता है, भी उनकी जान बख्श दी गई। पुनर्वास के बाद उनको तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इस ठुकरा दिया। इसकी वजह यह थी कि तिब्बत और दलाई लामा, जो कि कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ 1959 में हुई एक जनक्रांति के बाद निर्वासित होकर भारत चले गए थे, के बारे में चीन की स्थिति और नीतियों की वह लगातार आलोचना कर रहे थे।

उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ को लगातार तमाम पत्र लिखे जिनमें उन्होने स्थानीय नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए "अलगाववाद" के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और तिब्बती समाज में दलाई लामा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं। उन्होंने हू से अनुरोध किया कि वह दलाई लामा को उनकी मातृभूमि वापस आने दें जिससे इस क्षेत्र में स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी।

गत 7 मार्च को हांगकांग स्थित न्यू सेंचुरी प्रेस ने उनकी जीवनी प्रकाशित की जिसमें उन्होंने फिर चीन से यह अनुरोध किया है कि वह दलाई लामा से समझौता करे और तिब्बत मसले को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करे। अपनी जीवनी 'अ लांग वे तो इक्वलिटी ऐंड यूनिटी' (समानता और एकता के लिए लंबी यात्रा) पर उन्होंने तीन साल तक काम किया। किताब के प्रकाशक बाओ पु ने एससीएमपी डॉट कॉम से कहा, "उन्हें इस किताब की प्रूफ रीडिंग का मौका नहीं मिला जिसकी वजह से हमने पूरी किताब को जैसे का तैसा प्रकाशित कर दिया है।"

खबर में बताया गया है कि जीवनी में उन्होंने यह लिखा है कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के कई सदस्यों से निवेदन किया था कि वे "दलाई लामा के नेतृत्व में गए हजारों निर्वासित तिब्बती साथियों को घर लौटने और शांति से जीने तथा काम करने की इजाजत दें।" हालांकि, उनकी इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया।

"हम चीनी साम्राज्य की तरफ जाने वाली सड़क पर नहीं चल सकते" शीर्षक वाले एक अध्याय में वह चेतावनी देते हैं कि चीन को तिब्बती जनसंख्या पर अपने शासन को पुख्ता करने के लिए हिंसा और आर्थिक विकास का सहारा नहीं लेना चाहिए। न्यू सेंचुरी प्रेस ने इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बदनाम महासचिव झाओ जियांग की जीवनी प्रकाशित की थी।

निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 31 मार्च को कहा कि फुनवांग की निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरा दुःख हुआ है। परमपावन ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह दिखा दिया कि तिब्बती विरासत पर गर्व करते हुए भी कोई व्यक्ति "सच्चा कम्युनिस्ट" हो सकता है।

उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि, "कम्युनिस्ट आदर्शो पर उनके दृढ़ता से चलने के बावजूद चीनी प्रशासन ने फुंत्सोग वांगयाल के तिब्बती पहचान के प्रति समर्पण को नकारात्मक रूप में ही देखा जिसकी वजह से उन्हें 18 साल तक कैद में बिताने पड़े।"

फुनवांग पिछले साल जुलाई से ही बीजिंग के एक अस्पताल में थे और हाल में उनके फेफड़ों में कुछ समस्या हो गई थी। रायटर्स से उनके पुत्र फुनखम ने फोन पर बताया, "अपनी मौत तक वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनकी मौत के बाद हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए परंपरागत तिब्बती संस्कृति के मुताबिक लामाओं को बुलाया था। ◆

स्पॉइलिंग तिब्बतः चाइना ऐंड रीसोर्स नेशनलिज्म ऑन दि रूफ ऑफ दि वर्ल्ड

लेखकः गैब्रिएल लैफिट्टे
समीक्षकः केरी ब्राउन

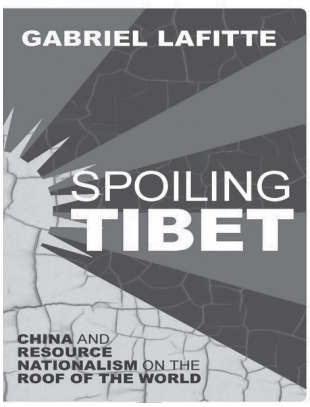

कुछ साल पहले मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजी के प्रोफेसर के पास बैठा हुआ था। हम चीन के संसाधन संपत्तियों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "चीन के पास तो ऐसे बहुत कम संसाधन हैं जिनका दोहन आसानी से किया जा सके।" मैंने शीक्यांग और आंतरिक मंगोलिया के संसाधनों के बारे में पूछा। वे कुछ देर तक चुप रहे फिर बोले, "हां यह तो है, लेकिन उन्हें हासिल करना भी कठिन है और चीन के पास इसे हासिल करने के लिए किफायती तकनीक नहीं है। यही बात तिब्बत के साथ भी है। हर कोई यह सोचता है कि वहां कीमती धातुओं का अतिशय भंडार है, लेकिन उनको हासिल कर पाना बहुत कठिन है।"

गैब्रिएल लैफिट्टे की पुस्तक स्पॉइलिंग तिब्बत इस बात का समर्थन करती है। हालांकि, उनका निष्कर्ष यह है कि स्थानीय प्रशासन के साथ किसी तरह के केंद्र–राज्य रिश्ते न होने, अन्वेषण करने वालों की लालच की वजह से तिब्बत का पठार– जो कि चीन के भौगोलिक क्षेत्र के करीब एक चौथाई के बराबर है– गहन और बर्बादी को जन्म देने वाले खनन एवं निष्कर्षण परियोजनाओं की स्थली बन सकता है।

लैफिट्टे अपनी बात को बहुत साफ तरीके से कहते हैं और बहुत से तिब्बती लोगों–जो ऐसी परियोजनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं–को सीधे बोलने का मौका देते हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों के लिए तिब्बत का पठार, समुद्र तल से चार–पांच किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित–एक ऐसी विशिष्ट आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सेतु है। घुमंतू जीवन पद्धति–जिसका पालन वे हजारों साल से कर रहे हैं– ने इस इलाके की पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा था। एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे और संसाधनों को इस्तेमाल इतने किफायत से करते थे कि वे खत्म नहीं होते थे।

लैफिट्टे इस बात पर जोर देते हैं कि देशज तिब्बती समुदाय आधुनिकता के अपने स्वरूप का पालन करते थे, वे आधुनिकता के शिकार नहीं थे और कभी भी उस जमीन के इस्तेमा की कोशिश नहीं करते थे, जहां वह रहते थे।

उन्होंने यह दिखाया है कि खनन और सोने व अन्य कीमती धातुओं के साथ काम करना तो तिब्बती संस्कृति में शताब्दियों से गहराई से समाहित है। केंद्रीकृत चीन सरकार की आधुनिकता की जो दृष्टि है वह काफी हद तक विकसित देशों से उधार ली गई है और बाद में इसे पूरे चीन में लागू किया गया है, लेकिन इसे स्थानीय दशाओं में लागू करना आसान नहीं है। वह तर्क देते हैं कि सरकार–खासकर वर्ष 1989 और 2008 की जनक्रांतियों के बाद– स्थानीय आंदोलनकारियों पर काफी गुस्से से प्रतिक्रिया कर रही है और उन्हें अलगाववादी बताने की कोशिश करती है, जबकि तथ्य यह है कि वह तिब्बती इलाके को जिस तरह से अतिशय संसाधनों का दोहन कर लूट रही है वह बाकी चीन के लिए भी बर्बादी बन सकती है। चीन का महत्वपूर्ण और अतिशय दोहन होने वाला जल संसाधन तिब्बत के पठार से आता है। इस जल संसाधन को उसके स्रोत या स्रोत के करीब प्रदूषित करने से बाकी चीन के हिस्से वाला जल में भी विषाक्त हो जाएगा।

तिब्बत मसले के काफी विवादास्पद राजनीति में नंगे हो चुके चीन के लिए ऐसी पर्यावरण चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। लैफिट्टे ने ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह व्याख्या करने में नहीं पड़े हैं कि तिब्बत पर किसकी प्रभुसत्ता है और कब और कैसे यह चीनी साम्राज्य के कब्जे में आ गया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि किस तरह से खनन उद्योग और उसके मौजूद दस्तूर तिब्बत के लिए भारी खतरा पैदा कर रहे हैं। अब इस इलाके में यातायात का बुनियादी ढांचा–सड़क और रेलवे– काफी विकसित हो चुका है, जिससे इस इलाके में जोखिम के साथ खनन करने वालों को और प्रोत्साहन मिल सकता है। लैफिट्टे ऐसे कई खनन कार्यों को अवैध और भारी नुकसान करने वाला बताता है जो कि चीनी कानून का किसी भी तरह से पालन नहीं करते।

ऑक्सफोर्ड के जिस जियोलॉजिस्ट से मैं कुछ साल पहले मिला था, वे बिल्कुल सही थे। तिब्बत में मुख्य धातु और खनिज भंडार के किसी भी परीक्षण से यह संकेत नहीं मिला है कि वहां कोई ऐसे खदान हैं जो कि दुनिय के शीर्ष 20 में जगह रखते हों। इस वजह से ही चीन की सरकारी खनन कंपनियां चिली, एशिया के दूसरे देशों या अफ्रीका के खदानों में निवेश कर रही हैं। वहां की भूगर्भ स्थित और भंडारों तक पहुंच थोड़ी आसान है और इसी प्रकार आपूर्ति श्रृंखला भी। दूसरी तरफ, तिब्बत में इन भंडारों तक पहुंच के लिए बड़े पैमाने पर चट्टानों और धरती में विस्फोट करने होंगे।

केवल माआवोदियों की प्रकृति के बारे में हेकड़ी पर भरोसा करने वाले लोग ही यह मान सकते हैं कि उनकी मौजूदा तकनीक कारगर है। तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के प्रबंधन के लिए वर्ष 2010 में बीजिंग में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बारे में बताते हुए लैफिट्टे यह दिखाते हैं कि यह हेकड़ी केंद्र सरकार की सोच में भी हावी है। उनके लिए तिब्बत एक ऐसा इलाका है जिसे गहन रेल और सड़क नेटवर्क विकसित करके इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां भी इसी तरह की बड़ी शहरीकरण परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं, जो कि बाकी देश में बड़े पैमाने पर चल रही हैं।

यह एक उपयुक्त समय पर और अच्छे से लिखी गई पुस्तक है जो सारगर्भित है और कई उदाहरणों से भरी हुई है। बीजिंग और तिब्बत के प्रगतिशील सोच के अधिकारियों को इसमें उठाए गए मसलों के बारे में जानना चाहिए और यह जानना चाहिए कि तिब्बती इलाके के पर्यावरण के कुप्रबंधन की पूरी संभावना है। अभी तक तो राजनीति ही इस देश, क्षेत्र और लैफिट्टे के मुताबिक पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। उम्मीद है कि यह पुस्तक इस मसले के बारे में एक जानकार, कम पक्षपाती बहस को बढ़ावा देगी।

लैफिट्टे इस बात पर जोर देते हैं कि अभी भले गलत चीजें हो रही हों, लेकिन उन्हें संभाला और सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि इनका समाधान नहीं किया गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज नही तो कल इसके गंभीर नतीजे होंगे। ◆

(केरी ब्राउन सिडनी यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर, चीनी राजनीति के प्रोफेसर और यूरोप चाइना रिसर्च ऐंड एडवाइस नेटवर्क के लीडर हैं। हाल में उन्होंने हू जिनताओः चाइनाज साइलेंट रूलर नामक पुस्तक लिखी है।)